गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 320
दि. 24.03.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

युद्ध के मुहाने पर ट्रंप का 'पॉज' बटन: ईरान पर हमले 5 दिन के लिए टले, वैश्विक तेल संकट टला

वाशिंगटन। पश्चिम एशिया में तनाव की आग लगातार भड़की हुई है और दुनिया के बड़े हिस्सों में तेल एवं ऊर्जा संकट की आशंका पैदा कर चुकी है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमलों को 5 दिन के लिए टालने का निर्णय लिया है, जिसे विशेषज्ञ 'राजनयिक खिड़की' का संकेत मान रहे हैं। यह कदम ट्रंप प्रशासन द्वारा रणनीतिक रूप से उठाया गया है, ताकि वार्ता के माध्यम से तनाव को कुछ समय के लिए कम किया जा सके और वैश्विक तेल बाजार को स्थिरता मिल सके।

28 फरवरी 2026 को ट्रंप प्रशासन ने 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' की घोषणा की थी, जिसके तहत ईरान के प्रमुख सैन्य और ऊर्जा ठिकानों पर लक्षित हमले किए जाने थे। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों और ट्रंप के निकट सूत्रों के अनुसार, इस ऑपरेशन को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना था। लेकिन सोमवार को अचानक ट्रंप ने इस योजना को पांच दिनों के लिए टाल दिया और इसे "बेहद सकारात्मक और उत्पादक बातचीत का नतीजा" बताया।

इस निर्णय के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकेबंदी और तेल आपूर्ति का संकट है। ईरान ने अमेरिकी धमकियों के जवाब में इस संकरे समुद्री मार्ग को बंद कर दिया था, जिससे दुनिया के कुल तेल और गैस का करीब 20% हिस्सा प्रभावित हो गया। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक तेल की कीमतें असमान्य रूप से बढ़ गई थीं। भारत, चीन और रूस जैसे देशों के ऊर्जा टैंकर इस नाकेबंदी के चलते फंसे हुए थे। हालांकि, ईरान ने इन देशों के जहाजों को निकलने की सीमित छूट दी है, लेकिन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बना हुआ

है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्षेत्रीय खतरे और आपसी प्रतिक्रिया का समीकरण है। ट्रंप के पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की धमकी के जवाब में ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकेर कलीबाफ ने चेतावनी दी थी कि अगर उनके बिजली घरों पर हमला हुआ, तो पूरे खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा और जल संयंत्रों को निशाना बनाया जाएगा। इससे पूरे क्षेत्र में अंधेरा छाने और पानी की आपूर्ति ठप होने का खतरा उत्पन्न हो गया था।

तीसरा और निर्णायक कारण आर्थिक दबाव है। इस युद्ध की वजह से अमेरिकी खजाने पर प्रतिदिन लगभग आधा अरब डॉलर का बोझ पड़ रहा है। ईरान में हुई तबाही और अमेरिकी सैन्य प्रयासों के चलते यह खर्च लगातार बढ़ रहा है। इस आर्थिक दबाव ने ट्रंप प्रशासन को वार्ता के लिए बाध्य किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया है कि यह युद्ध टालना फिलहाल इस सप्ताह होने वाली गोपनीय वार्ताओं की सफलता पर निर्भर करेगा। यदि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह खोलने और अपनी सैन्य गतिविधियों को कम करने पर सहमत होता है, तो यह कदम स्थायी तौर पर तनाव कम कर सकता है। अमेरिकी रणनीतिकारों का मानना है कि ट्रंप के 'पॉज' निर्णय से केवल सैन्य टकराव टला है, लेकिन राजनयिक समाधान की दिशा में दबाव बढ़ गया है। ओमान में चल रही गोपनीय वार्ताओं में दोनों पक्ष सुरक्षा आश्वासन, तेल आपूर्ति और क्षेत्रीय प्रभाव के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें शामिल देशों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ईरान होर्मुज की नाकेबंदी पूरी तरह खोलता है और अपनी सैन्य गतिविधियों में कमी लाता है।

इस कदम से वैश्विक बाजारों में अस्थिरता थोड़ी कम हुई है। कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट देखी गई और वित्तीय संस्थानों ने राहत की सांस ली। साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध के डर से दुनिया के शेयर बाजार भी प्रभावित थे, जो फिलहाल स्थिर दिख रहे हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन ने यह फैसला न केवल सैन्य दृष्टि से लिया है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था और अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा को देखते हुए भी एक रणनीतिक कदम है। अगर यह वार्ता सफल रहती है, तो न केवल खाड़ी देशों में स्थिरता आएगी, बल्कि भारत, चीन और यूरोपीय देशों के लिए ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी।

हालांकि, इस 'पॉज' का मतलब यह नहीं है कि संघर्ष समाप्त हो गया है। अमेरिकी और ईरानी दोनों पक्ष अभी भी अपने सैन्य और रणनीतिक विकल्प बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले पांच दिनों में होर्मुज के रास्ते खुलते हैं या नहीं, और दोनों पक्ष वार्ता में कितने सहमति बिंदु तय कर पाते हैं, यह तय करेगा कि संघर्ष कब तक स्थायी रूप से टला रहेगा।

इस बीच, ट्रंप प्रशासन और ईरानी नेतृत्व के बीच वार्ता का महत्व इस तथ्य में भी है कि पिछले 24 दिनों में ईरान में 2,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और इजरायल व अमेरिका के कई नागरिक भी प्रभावित हुए हैं। ईरान का दावा है कि 81,000 से अधिक घर युद्ध के कारण तबाह हो गए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में पांच दिन का टालना केवल समय खरीदने के समान है, ताकि दोनों पक्ष शांति वार्ता के लिए तैयार हो सकें।

विश्व समुदाय ने इस कदम को स्वागत योग्य बताया है, क्योंकि सीधे सैन्य हमले की स्थिति में पूरे क्षेत्र में अराजकता फैल सकती थी। संयुक्त राष्ट्र और कई यूरोपीय देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और वार्ता के माध्यम से समाधान खोजने की अपील की है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि ट्रंप द्वारा ईरान पर हमले को पांच दिनों के लिए टालने का फैसला एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। यह कदम न केवल पश्चिम एशिया में युद्ध के जोखिम को कम करता है, बल्कि वैश्विक तेल और ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब दुनिया की निगाहें ओमान में चल रही गोपनीय वार्ताओं पर टिकी हैं, जहां तय होगा कि क्या यह 'पॉज' केवल क्षणिक राहत है या स्थायी शांति की शुरुआत।

केरल में 'मुहर विवाद' ने उठाए सवाल, चुनाव आयोग ने कहा सिर्फ क्लेरिकल एरर

तिरुवनंतपुरम। केरल में चुनावी राजनीति की गर्मी बढ़ते ही एक नया विवाद सामने आया है, जिसने राज्य में सभी राजनीतिक दलों और आम जनता की संवेदनाओं को झकझोर दिया है। मामला 2019 के एक चुनाव आयोग के पत्र से जुड़ा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) केरल यूनिट की मुहर लगी दिखाई दी। इस दस्तावेज के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विपक्षी दलों ने इसे गंभीर चूक करार दिया और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने इसे केवल एक तकनीकी या क्लेरिकल एरर बताते हुए तुरंत सुधार की कार्रवाई की। इस विवाद ने राज्य में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है और आगामी चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है।

यह विवाद सीपीआईएम द्वारा दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने के बाद सामने आया। सीपीआईएम ने दावा किया कि इस पत्र में आयोग की बजाय भाजपा की मुहर लगी थी। दस्तावेज में दिखाया गया था कि 19 मार्च 2019 को चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को एक पत्र भेजा था, जिसमें हलफनामे के साथ भाजपा की मुहर लगी हुई थी। पार्टी का कहना था कि इस पत्र की प्रति कई राजनीतिक

दलों को भेजी गई, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग के दस्तावेजों में किसी बाहरी हस्तक्षेप की गुंजाइश बनी हुई थी। कांग्रेस ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी और सवाल उठाया कि चुनाव आयोग के दस्तावेजों में भाजपा की मुहर कैसे पहुंच गई और क्या इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर असर पड़ेगा।

चुनाव आयोग ने विवाद पर तत्काल सफाई दी। आयोग के केरल कार्यालय ने बताया कि यह पूरी तरह एक क्लेरिकल एरर थी। भाजपा केरल यूनिट ने हाल ही में एक पुरानी गाइडलाइन की कॉपी जमा की थी, जिस पर उनकी मुहर लगी थी। गलती से यही दस्तावेज अन्य दलों को भेज दिया गया। आयोग ने कहा कि जैसे ही गलती का पता चला, 21 मार्च को नया पत्र जारी कर गलत दस्तावेज वापस ले लिया गया। सभी राजनीतिक दलों, जिला चुनाव अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को इस सुधार की सूचना दे दी गई। आयोग ने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी गलती न हो, इसके लिए विशेष सावधानी बरती जाएगी।

हालांकि, विपक्ष इस सफाई से संतुष्ट नहीं है। सीपीआईएम ने आरोप लगाया कि क्या अब चुनाव आयोग और भाजपा एक ही पावर सेंटर से चल रहे हैं। कांग्रेस ने भी कहा कि यह केवल तकनीकी गलती नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरा हो सकती है। विपक्ष का तर्क है कि इस तरह की चूक मतदाताओं के बीच चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर अविश्वास पैदा कर सकती है और राजनीतिक दलों के लिए इस घटना को हथियार बनाने का अवसर भी दे सकती है।

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि हालांकि यह एक क्लेरिकल एरर हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस घटना का तेजी से वायरल होना और विपक्ष द्वारा इसे बड़े पैमाने पर उठाना राज्य में राजनीतिक संवेदनशीलता को और बढ़ा रहा है। यह मामला केवल तकनीकी गलती नहीं रह गया, बल्कि राज्य में चुनावी प्रक्रिया, लोकतंत्र और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर बहस का मुद्दा बन गया है।

विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के दस्तावेजों में थोड़ी सी भी चूक राजनीतिक दलों के लिए बड़ा हथियार बन सकती है। केरल में अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए, विपक्षी दल इस मामले को चुनावी रणनीति में शामिल कर सकते हैं। आयोग ने मीडिया और जनता से अपील की है कि इस तकनीकी गलती को बढ़ा-चढ़ाकर पेश न किया जाए और इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर अविश्वास का माहौल न बने।

इस विवाद ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि चुनाव आयोग को न केवल तकनीकी गलतियों को सुधारना होगा, बल्कि अपनी प्रक्रिया और दस्तावेजों की निगरानी को और सख्त बनाना होगा। विपक्ष का कहना है कि केवल क्लेरिकल एरर कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इससे जनता में शंका उत्पन्न होती है और चुनावी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। ऐसे समय में जब राज्य में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, यह विवाद राजनीतिक दलों के बीच तनाव और आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति पैदा कर सकता है।

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा केरल की मुहर वाले पत्र का मामला राज्य में राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन सकता है। सीपीआईएम और कांग्रेस इस घटना को लेकर लगातार सवाल उठाएंगे और इसे चुनावी रणनीति के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर सकते हैं। आयोग ने साफ किया है कि यह केवल तकनीकी गलती थी और इससे चुनाव प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि केरल में भाजपा की मुहर वाले पत्र का विवाद राज्य में राजनीतिक हलचल पैदा कर चुका है। विपक्ष इसे लोकतंत्र और चुनाव आयोग की निष्पक्षता के लिए खतरा मान रहा है, जबकि आयोग इसे सिर्फ क्लेरिकल एरर करार देकर सुधार भी कर चुका है। हालांकि, राज्य में चुनावी माहौल और विपक्ष की सतर्कता इसे लंबे समय तक सुर्खियों में बनाए रख सकती है।

तेहरान में इजरायल के हमलों ने बढ़ाई खतरनाक स्थिति, रिहायशी इलाकों में मौत और अफरा-तफरी

तेहरान। मध्य-पूर्व की नाजुक स्थिति एक बार फिर गंभीर मोड़ पर पहुंच गई है। सोमवार तड़के इजरायल द्वारा ईरान की राजधानी तेहरान और उसके आसपास के शहरों पर किए गए ताबड़तोड़ हवाई हमलों ने पूरे क्षेत्र में भय और असुरक्षा की लहर दौड़ा दी है। इन हमलों में रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया, जिससे छह लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग घायल हुए। इस हमले के बाद काले धुएं का गुबार शहर के आसमान में फैल गया और राजधानी के पूर्वी हिस्से में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

ईरानी मीडिया और स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, खोर्रमबाद और उत्तरी तेहरान के पॉश इलाकों में इजरायल के हवाई हमलों से कई इमारतें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं। राहत और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुट गए हैं। रिहायशी इलाकों पर हमला होने से आम नागरिकों में खौफ का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक हुए धमाके और इमारतों के गिरने की आवाज ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। इस हमले के बाद कई सड़कें बंद कर दी गई हैं और प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाएं सक्रिय कर दी गई हैं।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के बाद कहा कि ईरानी सरकार और उसके मिलिशिया नेटवर्क के खिलाफ लंबी लड़ाई जारी रहेगी। नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि इजरायल इस क्षेत्र में सुरक्षा और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस बीच, लेबनान में हिज़बुल्लाह के खिलाफ इजरायली जमीनी अभियान में भी तेजी देखी गई है। सैनिक और हथियारों की

तैनाती बढ़ाई गई है और दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है।

ईरान के सर्वोच्च नेता मोज़तबा खामेनेई भी हमलों की चपेट में आए। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, उन्हें मामूली चोट लगी है, लेकिन उनका स्वास्थ्य स्थिर है। हालांकि, वह फिलहाल किसी भी सार्वजनिक या आधिकारिक संदेश का जवाब नहीं दे रहे हैं। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि खामेनेई सुरक्षित स्थान पर हैं और उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। उनका गैर-मौजूदगी का असर देश की राजनीतिक और सैन्य प्रतिक्रिया पर भी पड़ा है, क्योंकि उनके निर्णय और आदेश इस स्थिति में महत्वपूर्ण हैं।

वहीं, सऊदी अरब की ओर भी मिसाइलें दागी गईं। रियाद के रक्षा मंत्रालय की जानकारी के अनुसार, दो बैलिस्टिक मिसाइलें सऊदी क्षेत्र की ओर भेजी गईं। इनमें से एक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, जबकि दूसरी सुनसान इलाके में गिरी, जिससे बड़ी तबाही टल गई। इस घटना ने साफ कर दिया है कि इस क्षेत्र में तनाव के कारण सभी पड़ोसी देशों की सुरक्षा भी खतरे में है और कोई भी संवेदनशील मिसाइल हमला व्यापक राजनीतिक और सैन्य संकट पैदा कर सकता है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इजरायल ने इन हमलों में उच्च सटीकता वाले हथियारों का उपयोग किया। उनका लक्ष्य मुख्य रूप से ईरानी सैन्य ठिकानों और मिसाइल डेवलपमेंट साइटों को नुकसान पहुंचाना था, लेकिन रिहायशी इलाके भी अप्रत्याशित रूप से प्रभावित हुए। इससे नागरिक हताहतों की संख्या बढ़ी है और राहत कार्यों में कई चुनौतियां सामने आई हैं। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वे इस हमले की पूरी जांच कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस हमले के राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव भी गंभीर हैं। तेल और गैस के वैश्विक बाजार में यह घटना तत्काल असर डाल सकती है, क्योंकि ईरान खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण मार्ग नियंत्रित करता है। हमलों और मिसाइल हमलों के कारण तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया और वैश्विक निवेशक चिंतित हैं। भारत, चीन और अन्य ऊर्जा आयातक देशों ने भी इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस हमले के बाद मध्य-पूर्व में स्थिति और अस्थिर हो सकती है। ईरान और इजरायल दोनों ही अपने-अपने गठबंधन देशों के साथ रणनीतिक और सैन्य संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस संघर्ष का सीधा असर वहां रहने वाले आम नागरिकों और पड़ोसी देशों की सुरक्षा पर पड़ रहा है। राहत कार्यों में शामिल स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां कह रही हैं कि शहर के पूर्वी हिस्सों में बचाव कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

इस हमले ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मध्य-पूर्व में शांति की संभावना फिलहाल कम है। इजरायल और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है और इससे क्षेत्रीय राजनीतिक स्थिरता खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इस स्थिति पर चिंता जताई है और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है।

संक्षेप में, तेहरान पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों ने न केवल ईरानी राजधानी को हिला कर रख दिया है, बल्कि पूरे मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ा दिया है। रिहायशी इलाकों में हुए हमलों से छह लोगों की मौत और दर्जनों घायल हुए हैं, जबकि महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य फैसलों में भी प्रभाव पड़ा है। मिसाइल हमलों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं ने इस स्थिति को और जटिल बना दिया है। फिलहाल राहत कार्य जारी हैं, लेकिन संकट की स्थिति लंबे समय तक बनी रह सकती है और दुनिया की नजरें इस संघर्ष पर टिकी हैं।

संपादकीय

मितव्ययिता का दिखावा

हिमाचल प्रदेश इस समय एक गहरे वित्तीय संकट से गुजर रहा है, और इस संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों ने एक व्यापक बहस को जन्म दे दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ नौकरशाहों के वेतन में कटौती का निर्णय इसी बहस के केंद्र में है। पहली नजर में यह फैसला त्याग और जिम्मेदारी का प्रतीक प्रतीत होता है, लेकिन जब इसे आर्थिक वास्तविकताओं की कसौटी पर परखा जाता है, तो इसकी प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के वेतन में 50 प्रतिशत, मंत्रियों के वेतन में 30 प्रतिशत और विधायकों के वेतन में 20 प्रतिशत की कटौती छह महीने की अवधि के लिए लागू की है। इस कदम को सरकार ने एक संदेश के रूप में प्रस्तुत किया है कि वह भी आर्थिक अनुशासन का पालन करने के लिए तैयार है। यह निर्णय राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली हो सकता है, क्योंकि यह जनता के बीच यह भावना पैदा करता है कि नेतृत्व स्वयं भी कठिनाइयों को साझा कर रहा है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से यह कदम अत्यंत सीमित प्रभाव वाला है। यदि हम आंकड़ों पर नजर डालें, तो हिमाचल प्रदेश का राजकोषीय घाटा हजारों करोड़ रुपये में है। ऐसे में वेतन कटौती से होने वाली संभावित बचत, जो कुल मिलाकर कुछ सौ करोड़ रुपये तक सीमित रह सकती है, इस विशाल घाटे के मुकाबले नगण्य ही है। इसका अर्थ यह है कि यह कदम राज्य की वित्तीय स्थिति में कोई ठोस सुधार लाने में सक्षम नहीं होगा। यह अधिक एक प्रतीकात्मक पहल है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक संदेश देना है, न कि वास्तविक आर्थिक समाधान प्रस्तुत करना। यह भी समझना जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश का वित्तीय संकट अचानक उत्पन्न नहीं हुआ है। यह वर्षों से चली आ रही संरचनात्मक समस्याओं का परिणाम है। राज्य की अर्थव्यवस्था लंबे समय से केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदानों पर निर्भर रही है। विशेष रूप से राजस्व घाटा अनुदान की समाप्ति ने इस निर्भरता को उजागर कर दिया है। जब तक यह अनुदान मिलता रहा, तब तक राज्य अपनी वित्तीय कमजोरियों को संतुलित कर पाता था, लेकिन इसके समाप्त होते ही वास्तविक स्थिति सामने आने लगी। राज्य के खर्चों का एक बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसे निश्चित व्ययों में जाता है। ये ऐसे खर्च हैं जिन्हें कम करना न केवल कठिन है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील है। इस कारण सरकार के पास व्यय में कटौती के सीमित विकल्प ही उपलब्ध हैं। ऐसे में वेतन कटौती जैसे कदम केवल सतही समाधान प्रदान करते हैं, जबकि मूल समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं।

वास्तविक समाधान के लिए राज्य को व्यापक आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, कर आधार का विस्तार करना अत्यंत आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन, जलविद्युत और बागवानी जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। यदि इन क्षेत्रों का सही तरीके से विकास किया जाए और उनसे जुड़े राजस्व तंत्र को मजबूत किया जाए, तो राज्य अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू सब्सिडी व्यवस्था का पुनर्गठन है। वर्तमान में कई ऐसी सब्सिडियां दी जा रही हैं, जो या तो अप्रभावी हैं या उनका लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। यदि इन सब्सिडियों को युक्तिसंगत बनाया जाए और उन्हें लक्षित तरीके से लागू किया जाए, तो सरकार अपने खर्चों को काफी हद तक नियंत्रित कर सकती है। तीसरा, राज्य को अपने पूंजीगत व्यय पर विशेष ध्यान देना होगा। सड़क, बिजली, जल आपूर्ति और डिजिटल अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में निवेश न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, बल्कि दीर्घकाल में राजस्व सृजन का आधार भी तैयार करता है। इसके विपरीत, यदि सरकार केवल राजस्व व्यय पर ध्यान केंद्रित करती है, तो आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है और वित्तीय संकट और गहरा सकता है। इस पूरे परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत के संघीय ढांचे से भी जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य भौगोलिक और आर्थिक दृष्टि से विशेष चुनौतियों का सामना करते हैं। उनकी राजस्व जुटाने की क्षमता सीमित होती है, जबकि विकास की लागत अधिक होती है। ऐसे में केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जब इस सहायता में अनिश्चितता होती है, तो उनकी आर्थिक स्थिरता भी प्रभावित होती है।

इसलिए यह आवश्यक है कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को अधिक संतुलित और पूर्वानुमानित बनाया जाए। राज्यों को मिलने वाली सहायता का ढांचा ऐसा होना चाहिए, जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखे और उन्हें दीर्घकालिक योजना बनाने में मदद करे। अंततः, वेतन कटौती जैसे कदम सरकार को अल्पकालिक राहत और नैतिक आधार तो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे दीर्घकालिक समाधान नहीं हैं। यदि हिमाचल प्रदेश को इस वित्तीय संकट से उबरना है, तो उसे साहसिक और संरचनात्मक सुधारों को अपनाना ही होगा। केवल प्रतीकात्मक उपायों के सहारे इस चुनौती का सामना करना संभव नहीं है।

युद्ध और कला व संस्कृति की क्षति

> "दुखद है कि युद्ध व संघर्ष में कला-संस्कृति व पुरातत्व से जुड़ी चीजों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। देश के बंटवारे के परिणाम स्वरूप हुई अदला-बदली में सांस्कृतिक कलाकृतियां का भी भारी नुकसान हुआ। ईरान भी हालिया युद्ध की कीमत चुका रहा है।

चंडीगढ़ के सेक्टर-9 में दिन-दहाड़े हुई एक हत्या को लेकर पिछले कुछ दिनों से शहर हिला और सहमा हुआ है। शहर का वह हिस्सा, जो अपने लाल सुर्ख बोगनवेलिया फूलों के लिए बेहतर जाना जाता है न कि गोलियों की बौछार के बाद स्थानीय गैंगस्टर के बिखरे लाल लहू के रंग से। चूंकि घटना के कई निष्कर्ष हो सकते हैं, बेहतर होगा कि हम आगे बढ़ें और पास के सेक्टर-10 की बात करें। यहां पिछले कुछ महीनों से ली कॉर्बूजिए द्वारा डिज़ाइन सरकारी संग्रहालय और आर्ट गैलरी में एक अलग किस्म की हिंसा जारी है। गनीमत है कि यहां जंग जुबानी रही—वह जगह जो कभी पंजाब के सबसे बड़े संस्कृति एवं कला विद्वान, बी.एन. गोस्वामी का अड्डा हुआ करती थी—वह नवीनीकरण योजना के कारण अब थमती नज़र आ रही है, जिसे हाल में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को सौंपा गया है; जिसकी लागत 30 करोड़ रुपये अनुमानित है।

जब आपके आस-पास हर तरफ़ अफ़रा-तफ़री मची हो, जिसमें ईरान के इस्फ़हान और खरग द्वीप पर हुई बमबारी भी शामिल है (ये दुनिया के दो सबसे खूबसूरत शहरों में से हैं, तुर्रा यह कि बमबारी दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र, अमेरिका द्वारा की जा रही है)—तो आप सवाल पूछ सकते हैं, क्या एक संग्रहालय मायने रखता है? या, क्या एक संस्कृति मायने रखती है? क्या तेल की कीमतों को कम रखना ज़्यादा ज़रूरी है? शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिकी अब खरग द्वीप पर कब्ज़ा करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि ईरानियों पर दबाव डालकर 'होर्मुज़ जल-डमरू' को फिर से खोला जा सके, जिससे होकर दुनिया का एक-तिहाई तेल गुज़रता है।

दरअसल, खरग द्वीप पर तेल-शोधन का एक विशाल संयंत्र है, जिसके माध्यम से ईरान के कुल निर्यात का 90 प्रतिशत तेल साफ किया जाता है। 13 मार्च को हुई बमबारी में, ट्रंप ने तेल सुविधाओं

को बख्श दिया था। लेकिन जैसे-जैसे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसी अफ़वाहें हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान को जल्द घुटने टेकने पर मजबूर करने को और भी कड़े कदम उठा सकते हैं।

केवल पांच मील लंबा होने के कारण, खरग द्वीप को एक आकर्षक विकल्प माना जा रहा है। उल्लेखनीय कि यह टापू 500 साल पुराने एक पुर्तगाली मठ का भी स्थान है—कुछ लोगों का मानना है कि इसका श्रेय 1507 में एशिया में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखने वाले जनरल अल्फ़ोंसो डी अल्बुकर्क को है। गोवा को भी अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से लिया था। इसके महज 16 साल बाद, 1526 में, यहीं उत्तर भारत में, फ़रगना के तैमूरी शहज़ादे ज़हीरुद्दीन मुहम्मद बाबर ने पानीपत में अपने ही एक मुस्लिम बिरादर, इब्राहिम लोदी को हराकर, जल्द ही खुद को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर डाला था।

आज जब हमारे टीवी स्क्रीन पर युद्ध के विस्फोटों के दृश्य चल रहे हैं, तो साम्राज्यों के उदय और पतन और उससे जुड़ी हिंसा को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। पंजाब भारत के उन दो राज्यों में से एक है (दूसरा है बंगाल), जिसकी गहरी यादें विभाजन की बर्बरता से जुड़ी हैं; राजकीय संग्रहालय और कलादीर्घाएं 1947 में देश के बंटवारे का जीती-जागती गवाह हैं। दुखद है कि बंटवारे के परिणामवश हुई हिंसा में दस लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और लगभग 1.7 करोड़ लोग एक देश से दूसरे मुल्क में विस्थापित हुए—हर चीज़, यहां तक कि सांस्कृतिक कलाकृतियों का भी बंटवारा हुआ था। प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस ने इसी माह खुशवंत सिंह की किताब 'ट्रेन टू पाकिस्तान' का संस्करण पुनः जारी किया है, इसकी प्रस्तावना बेजोड़ पाकिस्तानी इतिहासकार एफ.एस. ऐजाज़ुद्दीन ने लिखी है। लाहौर संग्रहालय ने अतुलनीय गांधार मूर्तियों का 60 प्रतिशत हिस्सा अपने पास रखा, जबकि शेष हिस्सा चंडीगढ़ संग्रहालय को मिला, जिसमें 627 कलाकृतियां थीं। यहां तक कि बुद्ध के पदचिह्न, जिन्हें 'बुद्धपाद' कहा जाता है, तीसरी सदी की ग्रेनाइट की बनी इस कलाकृति को भी नहीं बख्शा गया। एक पदचिह्न लाहौर ने अपने पास रखा और दूसरा चंडीगढ़ को मिला।

ऊपरी मंजिल पर चलिए, मूर्ति दीर्घा की ओर, तब आपको इस खूबसूरत संग्रहालय में लगातार हो रही वह हिंसा देखने को मिलेगी जिससे मेरा अभिप्राय है। पिछले कुछ समय से छत से पानी टपक रहा है, इसलिए प्राचीन मूर्तियों को ऐसे आवरण से ढक रखा है जो पहले कहीं और इस्तेमाल की जा चुकी 'बबल रैप शीट' जैसा है। काम अभी भी बेतरतीब और धीरे-धीरे चल रहा है।

कई सौ साल पुरानी बोधिसत्व की खड़ी मूर्ति पर सुतली से बंधा बबल रैप शीट हटाते हुए एक परिचायक ने कहा 'इधर देखिए,' और साथ ही यह भी जोड़ा कि उसे प्लास्टिक की पन्नी हटाने की मनाही है, लेकिन मैं देखने की इच्छुक थी। संग्रहालय की नई व मिलनसार निदेशक, ईशा कंबोज का कहना है कि वह संग्रहालय के जीर्णोद्धार योजना को पूरा करने के लिए पूरी तरह से दृढ़-संकल्पित हैं। खुशकिस्मती से, केंद्र सरकार इस बात से वाकिफ है कि भारत का उभरता मध्यम वर्ग देश के गौरवशाली अतीत में कितनी गहरी दिलचस्पी ले रहा है—दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय, 'युगे युगीन', नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को दफ्तरों से खाली करने के बाद वहां आकार लेने लगा है। चंडीगढ़ संग्रहालय के लिए, 'प्रधानमंत्री संग्रहालय' यानी भारत के प्रधानमंत्रियों पर बना संग्रहालय, जो कभी नेहरू संग्रहालय हुआ करता था— को नमूने के तौर पर माना जा रहा है।

विभाजन के दौरान सांस्कृतिक धरोहरों का बंटवारा एक अजीब-सी ज़िद तक ही सीमित रहा—सिंधु घाटी में मिले जेड और अगेट (सुलेमानी पत्थर) से बने हार की कहानी बहुत कुख्यात है, उसको बीच से काटकर दो हिस्सों में बांट दिया गया। पाकिस्तान को उस हार के 10 जेड मनकों में 6 और पेंडेंट के 4 मनकों में 3 मिले, शेष भाग भारत के हिस्से आया।

सभ्यता की तबाही के दौर में—भला कौन 2003 में हुई मेसोपोटामिया की तबाही को भूल सकता है? प्राचीन इराक का वह पालना स्थल, जो टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के मध्य बसा था, और जिसे अमेरिकियों ने सद्दाम हुसैन को मारने की कोशिश में तबाह कर डाला था—ठीक वैसे ही, जैसा आजकल अमेरिका और इस्राइल मिलकर ईरान के साथ कर रहे हैं; तो ऐसे में आप भारतीय और पाकिस्तानी नौकरशाही की उस अजीब-सी सूझ-बूझ के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। 'द गार्डियन' अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 'नीले शहर' के नाम से मशहूर इस्फ़हान में, 'चेहेल सोतून' नाम का 20 खंभों वाला फ़ारसी शैली के मंडप वाला बगीचा, 'अली कापू' महल, 'मस्जिद-ए-जामे' के अतिरिक्त 'नक़्श-ए-जहां' चौक के आसपास बनी कई अन्य मस्जिदें, पिछले दो हफ़्तों की बमबारी से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

2021 में अफ़गानिस्तान में तालिबान पुनः वापसी होने से पूर्व, मैंने से देखा था कि काबुल संग्राहलय के विरासत की साज-संभाल करने वाले कर्मियों ने कितनी शिद्दत-मेहनत के साथ ग्रेनाइट के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर बुद्ध की उन मूर्तियों को फिर से खड़ा किया था, जिन्हें 1996 में पहली बार शहर में घुसते ही तालिबानियों ने तोड़कर तबाह कर दिया था। हालांकि इस बार, तालिबान ने यह वादा किया है कि वे म्यूज़ियम के अंदर रखी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे।

शायद, एक दिन, इंसानियत की भावना ही विजयी होगी। जैसा कि सदा से होता आया है।

प्रेरणा

मन की विजय: आत्मबल से इतिहास बदलने की कहानी

मानव इतिहास में जितनी भी महान विजयगाथाएं लिखी गई हैं, उनमें एक अदृश्य लेकिन अत्यंत प्रभावशाली तत्व हमेशा मौजूद रहा है—आत्मबल। यह वह शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति या समाज को उसकी सीमाओं से परे जाकर असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा देती है। जब मन दृढ़ होता है, तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हों, सफलता की राह निकल ही आती है। आत्मबल केवल एक भावना नहीं, बल्कि वह आंतरिक ऊर्जा है जो हार और जीत के बीच का अंतर तय करती है।

एक समय ऐसा था जब पूरे यूरोप में यूनान की सेनाओं का आतंक छाया हुआ था। यूनानी सैनिकों को अजेय माना जाता था और उनके सामने आने वाले अधिकांश राज्य पहले ही मानसिक रूप से पराजित हो जाते थे। युद्ध का परिणाम तलवारों के टकराने से पहले ही तय हो जाता था, क्योंकि विरोधी पक्ष के मन में हार का भय गहराई तक बैठ चुका था। यह भय धीरे-धीरे एक ऐसी मानसिकता में बदल गया, जिसमें लोगों ने यह मान लिया कि यूनान को हराना असंभव है।

इस परिस्थिति में जूलियस सीज़र ने एक गहरी सच्चाई को पहचाना। उन्होंने देखा कि यूनान की असली ताकत उसकी सेना नहीं, बल्कि उसके विरोधियों की मानसिक कमजोरी है। लोग अपने आप को कमजोर और यूनानियों को अजेय मान बैठे थे। यह आत्महीनता ही उनकी पराजय का मूल कारण बन रही थी। सीज़र ने समझ लिया कि यदि इस मानसिकता को बदला जाए, तो युद्ध का परिणाम भी बदल सकता है।

सीज़र ने किसी बड़े सैन्य अभियान की बजाय सबसे पहले लोगों के मन को बदलने का प्रयास किया। उन्होंने रोम की दीवारों, चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर एक प्रेरणादायक वाक्य लिखवाया—"यूनानी फौजें तभी तक अजेय हैं, जब तक हम उनके सामने झुके हुए हैं। आओ, हम उठें और अपने आत्मबल को पहचानें।" यह वाक्य केवल शब्द नहीं था, बल्कि एक क्रांति का बीज था, जिसने धीरे-धीरे लोगों के भीतर आत्मविश्वास की नई रोशनी जगाई।

रोम के लोगों के भीतर जो डर और हीनता की भावना जमी हुई थी, वह धीरे-धीरे खत्म होने लगी। उन्होंने यह समझ लिया कि असली लड़ाई मैदान में नहीं, बल्कि उनके अपने मन के भीतर है। जैसे ही उन्होंने अपने भीतर छिपे साहस को पहचाना, उनकी सोच बदल गई। अब वे यूनान को एक अजेय शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखने लगे।

जब युद्ध का समय आया, तो रोम की सेना पहले की तरह भयभीत नहीं थी। उनके भीतर आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प था। उन्होंने पूरे साहस और रणनीति के साथ युद्ध लड़ा। परिणामस्वरूप, वह यूनानी सेना, जिसे अब तक अजेय समझा जाता था, पराजित हो गई। यह विजय केवल युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि आत्मबल की शक्ति का प्रमाण थी।

यह घटना हमें यह सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती हैं। जब हम अपने मन में हार मान लेते हैं, तो बाहरी दुनिया में जीत पाना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। आज के समय में भी यह सिद्धांत उतना ही प्रासंगिक है। हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं—कभी पढ़ाई में कठिनाई, कभी करियर में असफलता, तो कभी व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष। कई बार हम इन चुनौतियों से घबराकर प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। हम यह मान लेते हैं कि हम सफल नहीं हो सकते, और यही सोच हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। यदि हम अपने दृष्टिकोण को बदलें और आत्मबल को अपनाएं, तो हम इन कठिनाइयों को अवसर में बदल सकते हैं। आत्मबल हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। यह हमें गिरने के बाद फिर से उठने की शक्ति देता है और निरंतर प्रयास करते रहने की प्रेरणा देता है।

आत्मबल को विकसित करने के लिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। हमें नकारात्मक सोच को त्यागकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने देना चाहिए। इसके बजाय, हमें उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए और अपने गुणों को निखारना चाहिए।

इसके अलावा, आत्मबल का संबंध केवल व्यक्तिगत सफलता से नहीं है। यह समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब एक समाज के लोग आत्मविश्वासी और सशक्त होते हैं, तो वे मिलकर बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं, जहां आत्मबल से भरे लोगों ने अपने देश को संकट से उबारा और नई दिशा दी। इस संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को आत्मबल का महत्व सिखाएं। उन्हें यह समझाना जरूरी है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। यदि वे अपने भीतर विश्वास बनाए रखें, तो वे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

अंततः, आत्मबल ही वह शक्ति है, जो हमें हमारी वास्तविक क्षमता का एहसास कराती है। यह हमें यह सिखाती है कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उन्हें बदलने की क्षमता रखते हैं। जिस दिन हम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान लेंगे, उस दिन हमारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा।

इसलिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें बाहरी संसाधनों से ज्यादा अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। जब हम अपने आत्मबल को जागृत करते हैं और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में विजयी बनते हैं।

BRICS के विस्तार ने बढ़ाई भारत की ताकत, पश्चिमी देशों का टूट सकता है वर्चस्व

ब्रिक्स के विस्तार ने वैश्विक शक्ति संतुलन की बिसात पर ऐसा दांव चला है, जिसने पश्चिमी प्रभुत्व को खुली चुनौती दे दी है। भारत के लिए यह उभरती विश्व व्यवस्था में अपनी निर्णायक भूमिका दर्ज कराने का सुनहरा अवसर बन चुका है। आज जब दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रही है, तब ब्रिक्स का विस्तार भारत की सामरिक ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला कारक बनकर सामने आया है।पहले ब्रिक्स पांच देशों का समूह था, जिसकी कुल वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी लगभग 31 प्रतिशत के आसपास थी। लेकिन विस्तार के बाद इसमें नए सदस्य जुड़ने से यह आंकड़ा लगभग 37 से 40 प्रतिशत तक पहुँच गया है। जनसंख्या के लिहाज से भी यह समूह अब दुनिया की लगभग 45 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सीधा अर्थ है कि भारत अब ऐसे मंच का प्रमुख स्तंभ है जो आर्थिक, जनसंख्या और संसाधनों के मामले में पश्चिमी देशों को बराबरी की टक्कर दे सकता है।

भारत के लिए सबसे बड़ा सामरिक लाभ यह है कि ब्रिक्स के जरिए वह डॉलर आधारित वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के विकल्प को मजबूत करने में भूमिका निभा सकता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाएं पहले ही पश्चिमी वित्तीय संस्थानों के एकाधिकार को चुनौती दे रही हैं। यदि स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा मिलता है, तो भारत को विदेशी मुद्रा दबाव से राहत मिलेगी और उसकी आर्थिक संप्रभुता मजबूत होगी।

सामरिक स्तर पर भी यह विस्तार भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पश्चिम एशिया और अफ्रीका के कई नए सदस्य देशों के जुड़ने से भारत की पहुंच ऊर्जा संसाधनों, समुद्री मार्गों और रणनीतिक क्षेत्रों तक बढ़ेगी। यह वही क्षेत्र हैं जहां अब तक चीन अपनी पकड़ मजबूत करता रहा है। ब्रिक्स के भीतर सक्रिय भूमिका निभाकर भारत इस प्रभाव को संतुलित कर सकता है और खुद को एक भरोसेमंद शक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है।

अब सवाल उठता है कि इस वर्ष भारत में प्रस्तावित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन क्या मौजूदा वैश्विक तनावों के बीच संभव हो पाएगा? देखा जाये तो पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, रूस और पश्चिम के बीच टकराव, और अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा ने वैश्विक माहौल को बेहद जटिल बना दिया है। लेकिन इतिहास बताता है कि संकट के दौर में ही ऐसे मंचों की अहमियत बढ़ जाती है। संभावना यही है कि सम्मेलन आयोजित होगा, भले ही कुछ नेताओं की उपस्थिति प्रत्यक्ष की बजाय ऑनलाइन माध्यम से हो।

वैसे असल चुनौती यह नहीं है कि सम्मेलन होगा या नहीं, बल्कि यह है कि क्या सदस्य देश एक साझा एजेंडा पर सहमत हो पाएंगे? उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स के भीतर भी मतभेद हैं। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद, रूस और पश्चिम के बीच युद्ध एवं पश्चिम एशिया के देशों के संघर्ष इस मंच की एकता की परीक्षा ले रहे हैं। फिर भी, आर्थिक हित और वैश्विक संतुलन की जरूरत इन देशों को एक साथ बैठने के लिए मजबूर करती है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट ने ब्रिक्स की प्रासंगिकता को और बढ़ा दिया है। जहां पश्चिमी देश अक्सर पक्षपातपूर्ण रुख अपनाते दिखते हैं, वहीं ब्रिक्स एक संतुलित और बहुपक्षीय समाधान की बात करता है। भारत, जो खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, वह इस मंच के जरिए शांति पहल को निश्चित रूप से आगे बढ़ा सकता है।

वर्तमान वैश्विक संकटों के संदर्भ में भी देखें तो समाधान की दिशा में ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में भारत की भूमिका निर्णायक हो सकती है। भारत पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि वह संवाद, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान के आधार पर समाधान चाहता है। भारत यदि मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, तो वह न केवल अपनी वैश्विक छवि को मजबूत करेगा बल्कि ब्रिक्स को भी एक प्रभावी संकट समाधान मंच के रूप में स्थापित कर सकता है।

आंकड़ों की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ते हुए दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और अगले कुछ वर्षों में इसके तीसरे स्थान तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में ब्रिक्स के भीतर भारत की भूमिका केवल एक सदस्य की नहीं बल्कि एक दिशा तय करने वाली शक्ति की है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत की पहलें ब्रिक्स देशों के लिए मॉडल बन सकती हैं। बहरहाल, यह स्पष्ट है कि ब्रिक्स का विस्तार भारत के लिए एक रणनीतिक वरदान है, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। यदि भारत इन चुनौतियों को संतुलित करते हुए इस मंच का प्रभावी उपयोग करता है, तो वह न केवल अपनी वैश्विक ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है बल्कि एक नई विश्व व्यवस्था के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। यह समय भारत के लिए सिर्फ भागीदारी का नहीं, बल्कि नेतृत्व का है।

अभियान

राम की अनंत छवियाँ: भक्ति, भावना और लोकचेतना का विराट विस्तार

जब रामनवमी का पावन पर्व आता है, तो अयोध्या की धरती मानो भक्ति और भावनाओं के सागर में डूब जाती है। हर ओर एक ही ध्वनि गूंजती है—"भये प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी।" यह केवल एक चौपाई नहीं, बल्कि करोड़ों हृदयों की आस्था का स्पंदन है। भगवान राम केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि वे भारतीय मानस में रचे-बसे ऐसे आदर्श हैं, जिनकी छवियाँ समय, स्थान और भावनाओं के अनुसार निरंतर विस्तार पाती रही हैं।

राम की विशेषता यह है कि वे एक सीमित परिभाषा में बंधने वाले देवता नहीं हैं। वे जितने रामायण के नायक हैं, उतने ही लोकजीवन के भी। किसी के लिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो किसी के लिए करुणा और दया के सागर। कोई उन्हें आदर्श पुत्र, आदर्श राजा और आदर्श पति के रूप में देखता है, तो कोई उन्हें निर्बलों का बल और दीनों का सहारा मानता है। यही कारण है कि राम की भक्ति एकरूप नहीं, बल्कि बहुरूपा है।

अयोध्या के संतों की परंपरा में यह मान्यता रही है कि भगवान राम की छवि किसी एक व्यक्ति या संप्रदाय द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती। भक्तों को यह पूर्ण स्वतंत्रता है कि वे अपनी भावनाओं के अनुसार अपने राम की कल्पना करें। यही कारण है कि संत परंपरा में राम की उपासना अनेक भावों में की गई है—दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। यह विविधता ही रामभक्ति को इतना व्यापक और जीवंत बनाती है। कबीर जैसे संत ने राम को एक अद्वैत सत्ता के रूप में देखा। उनके लिए राम केवल अयोध्या के राजा नहीं, बल्कि वह परम तत्व हैं, जो हर कण में व्याप्त हैं। कभी वे कहते हैं, "हरि मोर पिउ, मैं राम की बहुरिया," तो कभी वे राम को अपनी जननी के रूप में अनुभव करते हैं—"हरि जननी मैं बालक तोरा।" इस प्रकार कबीर ने भक्ति के सभी पारंपरिक बंधनों को तोड़कर राम को एक सार्वभौमिक सत्ता के रूप में प्रस्तुत किया। इसी प्रकार महात्मा गांधी के लिए राम केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं थे, बल्कि सत्य, अहिंसा और नैतिकता के प्रतीक थे। उनका प्रिय भजन "रघुपति राघव राजा राम" इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने राम को एक ऐसे आदर्श के रूप में देखा, जो सभी धर्मों और समुदायों को जोड़ता है। उनके "ईश्वर अल्ला तेरो नाम" के संदेश में राम की वही सर्वसमावेशी छवि झलकती है, जो भेदभाव को मिटाकर एकता की राह दिखाती है।

रामकथा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह केवल भारत तक सीमित नहीं है। यह कथा दुनिया के 60 से अधिक देशों में विभिन्न रूपों में कही और सुनी जाती है। इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे देशों में, जहां बहुसंख्यक जनसंख्या अन्य धर्मों का पालन करती है, वहां भी रामकथा का मंचन होता है। इन प्रस्तुतियों में स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और यहां तक कि अन्य धर्मों के तत्वों का भी समावेश हो जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राम केवल एक धर्म के नहीं, बल्कि समस्त मानवता के नायक हैं।

फिलीपींस की रामकथा इसका एक अनूठा उदाहरण है, जिसमें इस्लामी परंपराओं के कई तत्व समाहित हो गए हैं। समय के साथ इन तत्वों का ऐसा मिश्रण हो गया है कि अब यह बताना कठिन हो जाता है कि कौन-सा तत्व किस परंपरा से आया है। फिर भी, इन विविधताओं के बावजूद रामकथा की मूल भावना एक ही रहती है—धर्म, सत्य और न्याय की विजय।

इतिहास के पन्नों में भी राम की यह सर्वसमावेशी छवि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब अंग्रेजों ने 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को सत्ता से हटाकर निर्वासित कर दिया, तब अयोध्या में उनके कुशलक्षेम के लिए राम से प्रार्थनाएं की गईं। यह उस गंगा-जमुनी तहजीब का उदाहरण है, जिसमें धर्म और संस्कृति के बीच कोई दीवार नहीं थी। नवाबों ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अयोध्या के मंदिरों को दान और जागीरें दीं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राम की भक्ति केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं रही।

भक्तिकाल के संत कवियों ने राम को जिस प्रकार अपनाया, वह उनकी भक्ति की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है। तुलसीदास की पंक्ति "जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी" इस सत्य को स्थापित करती है कि राम की अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकती है। कोई उन्हें निर्गुण ब्रह्म के रूप में देखता है, तो कोई सगुण साकार भगवान के रूप में। सूरदास, जो मुख्यतः कृष्णभक्त माने जाते हैं, उन्होंने भी अपने मन को राम की भक्ति में लगाने की प्रेरणा दी। यह इस बात का प्रमाण है कि भक्तिकाल में राम और कृष्ण के बीच कोई कठोर विभाजन नहीं था, बल्कि दोनों एक ही परम सत्य के विभिन्न रूप थे।

मीरा बाई की भक्ति में भी यह समन्वय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यद्यपि वे कृष्ण की उपासक थीं, लेकिन उन्होंने राम नाम की महिमा को भी स्वीकार किया। उनके लिए भक्ति का मूल तत्व प्रेम था, और इस प्रेम में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। "पायो जी मैंने राम रतन धन पायो" जैसे पद इस बात का प्रमाण हैं कि राम नाम उनके लिए भी उतना ही पवित्र और प्रिय था।

इसी परंपरा में रैदास और संत मलूकदास जैसे संतों ने भी रामभक्ति को अपने-अपने ढंग से व्यक्त किया। रैदास के लिए तो मन ही पूजा और मन ही धूप बन गया—"मन ही पूजा, मन ही धूप।" यह विचार भक्ति को बाहरी आडंबरों से मुक्त कर उसे आंतरिक साधना का रूप देता है।

आधुनिक युग में भी राम की यह परंपरा जीवित रही। मैथिलीशरण गुप्त ने अपने महाकाव्य "साकेत" में राम को एक मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उन्होंने राम से प्रश्न किया—"राम, तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या?" यह प्रश्न केवल एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि राम के मानवीय और दैवीय दोनों स्वरूपों को समझने का प्रयास है। भारतेन्दु हरिश्चंद्र और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे साहित्यकारों ने भी राम को अपने-अपने दृष्टिकोण से चित्रित किया। निराला की "राम की शक्ति पूजा" में राम केवल एक देवता नहीं, बल्कि संघर्ष और साहस के प्रतीक बन जाते हैं। उन्होंने इस रचना के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के दौर में जनता को प्रेरित करने का कार्य किया।

अंततः यह कहा जा सकता है कि भगवान राम की सबसे बड़ी विशेषता उनकी अनंतता है। वे किसी एक रूप, एक विचार या एक परंपरा में सीमित नहीं हैं। वे हर युग, हर समाज और हर व्यक्ति के लिए नए अर्थ लेकर आते हैं। उनकी भक्ति में विविधता है, लेकिन उस विविधता में भी एकता का अद्भुत भाव छिपा हुआ है।

राम केवल अतीत के नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के भी मार्गदर्शक हैं। जब तक मानव समाज में सत्य, धर्म और न्याय की आवश्यकता बनी रहेगी, तब तक राम की प्रासंगिकता भी बनी रहेगी। यही कारण है कि "भये प्रगट कृपाला दीनदयाला" का उद्घोष केवल अयोध्या तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के हृदय में गूंजता रहेगा।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

विश्व टीबी दिवस: पीएम मोदी के 'टीबी मुक्त भारत' विजन का चैंपियन बना गुजरात, 92% इलाज सफलता दर के साथ राष्ट्रीय उन्मूलन अभियान में सबसे आगे

- 94% लक्ष्य हासिल: नीति आयोग के 1.40 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 1,31,801 टीबी मरीजों की सफलतापूर्वक पहचान कर किया पंजीकरण
- 49.10 करोड़ की वित्तीय सहायता: निरंतर पोषण सहायता सुनिश्चित करने के लिए 2025 में 92,921 मरीजों को दी गई प्रत्यक्ष वित्तीय मदद
- 4.49 लाख पोषण किट: 31,058 पंजीकृत सामुदायिक स्वयंसेवकों (निक्षय मित्रों) के मजबूत नेटवर्क के माध्यम से मरीजों को वितरित की गई पोषण किट
- 75.39 लाख लोगों की स्क्रीनिंग: सघन टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बड़े पैमाने पर सक्रिय परीक्षण किया गया, जिससे 1.63 लाख नए मामलों को सक्रिय देखभाल के दायरे में मिली सफलता

गांधीनगर : गुजरात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'टीबी मुक्त भारत' के विजन को तेजी से साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में, राज्य ने नीति आयोग द्वारा निर्धारित टीबी पंजीकरण और उपचार के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का 94% हासिल कर लिया है, जिससे इस बीमारी के उन्मूलन में एक राष्ट्रीय अग्रणी के रूप में राज्य की स्थिति मजबूत हुई है। इस स्वास्थ्य सफलता का पैमाना विश्व टीबी दिवस पर गुजरात स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा क्लिनिकल आंकड़ों में विस्तार से बताया गया है। वर्ष 2025 में 1,40,000 टीबी मामलों की पहचान करने के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य के मुकाबले, राज्य ने सफलतापूर्वक 1,31,801 मरीजों की पहचान की और उनका पंजीकरण किया। लेकिन यह प्रयास सिर्फ पहचान करने

तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि इसे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाया गया। पहचाने गए मरीजों में से 1,25,301 मरीजों को तुरंत सक्रिय उपचार के दायरे में लाया गया। निरंतर मेडिकल फॉलो-अप की बदौलत, 1,21,912 मरीजों ने अपना इलाज पूरी तरह से संपन्न किया, जिससे 91.74% की अत्यधिक सराहनीय क्लिनिकल रिकवरी दर हासिल हुई।

वित्तीय और पोषण सहायता से लड़ाई को मिली ताकत

यह मानते हुए कि टीबी के खिलाफ लड़ाई सिर्फ क्लीनिकों में नहीं बल्कि घरों में भी लड़ी जाती है, राज्य सरकार ने मरीजों के वित्तीय बोझ को काफी कम किया है। लंबे समय तक चलने वाला इलाज अक्सर आर्थिक कठिनाइयां लाता है, जिसके कारण कई बार मरीज बीच में ही इलाज छोड़ देते हैं। इससे निपटने के लिए, गुजरात सरकार ने अकेले 2025 में 92,921 टीबी मरीजों को 49.10 करोड़ की राशि वितरित की। निक्षय पोषण योजना के तहत, मरीजों को हर महीने 1,000 की महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य इलाज के दौरान उनके पोषण स्तर को बनाए रखना है।

इस वित्तीय मदद को अभूतपूर्व सामुदायिक समर्थन से और मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री के 'टीबी मुक्त भारत अभियान' से प्रेरित होकर, गुजरात ने राष्ट्रीय पोर्टल पर 31,058 निक्षय मित्रों (सामुदायिक स्वयंसेवकों और प्रायोजकों) को पंजीकृत करके स्वास्थ्य सहायता को सफलतापूर्वक जन-भागीदारी से जोड़ा है। 10,682 सक्रिय स्वयंसेवकों के प्रयासों से इन निक्षय मित्रों ने मरीजों को 4.49 लाख से अधिक पोषण किट वितरित की हैं, जो समुदाय-संचालित पोषण सहायता में गुजरात को देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बनाता है।

प्रोएक्टिव स्क्रीनिंग का महाभियान: 75.39 लाख लोगों की जांच, 1.63 लाख नए मरीजों की पहचान

दिसंबर 2024 में शुरू किए गए भारत सरकार के "100-दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन अभियान" का नेतृत्व करते हुए, राज्य ने बड़े पैमाने पर घर-घर जाकर सामुदायिक स्क्रीनिंग का काम किया। 20 मार्च 2026 तक, अविश्वसनीय रूप से 75.39 लाख लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इस सक्रिय अभियान ने सफलतापूर्वक 1,63,426 नए मरीजों की पहचान की है।

इतना ही नहीं, बीमारी के गंभीर होने या उनके समुदाय में फैलने से पहले ही उन्हें राज्य के मजबूत उपचार तंत्र में निर्बाध रूप से शामिल कर लिया गया है। नैदानिक दक्षता, वित्तीय सुरक्षा, सामुदायिक लामबंदी और सक्रिय प्रारंभिक पहचान के एक शक्तिशाली संयोजन के माध्यम से, गुजरात सिर्फ टीबी का इलाज ही नहीं कर रहा है, बल्कि इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक स्पष्ट और अनुकरणीय रास्ता भी तैयार कर रहा है।

भावनगर मंडल के 04 कर्मचारी डीआरएम संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में सुरक्षित रेल परिचालन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले चार कर्मचारियों को आज मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा द्वारा डीआरएम संरक्षा पुरस्कार (DRM Safety Award) से सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, भावनगर परा में आयोजित किया गया।

सम्मानित कर्मचारियों में श्री कन्हैयालाल कनाडा (प्वाइंट्समैन–धोलका), श्री घनश्याम सी. (प्वाइंट्समैन –लाठीदड स्टेशन), श्री सतीश जी. (प्वाइंट्समैन –बोटाद जंक्शन) तथा श्री सत्यजीत पाण्डेय (प्वाइंट्समैन–अलमपर स्टेशन) शामिल हैं। इन कर्मचारियों ने अपनी सतर्कता, सूझबूझ एवं त्वरित कार्रवाई से संभावित दुर्घटनाओं को टालते हुए रेल संरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सराहना करते हुए उन्हें अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्रोत बताया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की उच्च स्तर की प्रतिबद्धता एवं कर्तव्यनिष्ठा सुरक्षित रेल संचालन की आधारशिला है।

घटनाओं का संक्षिप्त विवरण:

श्री कन्हैयालाल कनाडा ने 10 मार्च 2026 को गाड़ी संख्या 20965 गांधीग्राम–भावनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस के एसएलआर से धुआँ निकलते देखा। उन्होंने तत्काल ट्रेन मैनेजर एवं स्टेशन मास्टर को सूचित किया, जिसके फलस्वरूप धोलका स्टेशन पर संबंधित कोच को अलग कर संभावित दुर्घटना को टाल दिया गया।

श्री घनश्याम सी. ने 20 नवंबर 2025 को लाठीदड स्टेशन पर एक मालगाड़ी के सातवें एवं आठवें वैगन में हॉट एक्सल की गंभीर स्थिति देखी। उन्होंने तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचना दी, जिसके बाद ट्रेन को रोका गया और आवश्यक सुधार कर सुरक्षित रवाना किया गया।

श्री सतीश जी. ने 12 नवंबर 2025 को बोटाद जंक्शन पर एक मालगाड़ी में हैंगिंग पार्ट देखा। उन्होंने तत्परता से लोको पायलट को खतरे का संकेत देकर ट्रेन रुकवाई तथा लटके हुए पार्ट को सुरक्षित कर ट्रेन को आगे बढ़ाया गया।

श्री सत्यजीत पाण्डेय ने 16 नवंबर 2025 को अलमपर स्टेशन पर एक मालगाड़ी के दो वैगनों में चिंगारी देखी। उन्होंने तुरंत डेंजर सिग्नल देकर ट्रेन रुकवाई, जांच में ब्रेक जाम पाया गया, जिसे ठीक कर सुरक्षित संचालन सुनिश्चित किया गया।

मंडल रेल प्रबंधक ने सभी सम्मानित कर्मचारियों को बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट कार्य करते रहने हेतु प्रोत्साहित किया।

पश्चिम रेलवे का भावनगर मंडल अपने कर्मचारियों की त्वरित सोच, साहस एवं सतर्कता की सराहना करता है, जिनके प्रयासों से न केवल रेल संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हुई, बल्कि संभावित दुर्घटनाओं को भी प्रभावी रूप से रोका जा सका।

अहमदाबाद में वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों के साथ "संवाद" कार्यक्रम आयोजित,यात्री सेवाओं एवं राजस्व वृद्धि पर विशेष जोर

पश्चिम रेलवे के वाणिज्य विभाग में कार्यरत रेल कर्मचारियों के साथ "संवाद" कार्यक्रम का आयोजन आज अहमदाबाद मंडल में किया गया। यह संवाद सत्र श्री तरुण जैन, प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, पश्चिम रेलवे एवं श्री वेद प्रकाश, मण्डल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद के नेतृत्व में आयोजित किया गया।

इस अवसर पर मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (यात्री विपणन) एवं मुख्य दावा अधिकारी, पश्चिम रेलवे श्री जगदीश प्रसाद, अपर मण्डल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्रीमती मंजु मीना, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, अहमदाबाद श्री अन्नू त्यागी सहित वाणिज्य विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे।

इसके अतिरिक्त, पश्चिम रेलवे के सभी मंडलों से वाणिज्य विभाग के कर्मचारी भी इस संवाद कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल हुए, जिससे यह सत्र व्यापक प्रतिनिधित्व एवं सहभागिता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्यालय स्तर के नेतृत्व एवं मंडल स्तर के कर्मचारियों के बीच सीधा संवाद स्थापित करना तथा यात्री विपणन (Passenger Marketing), बुकिंग, आरक्षण एवं कैटरिंग से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना था। साथ ही, इस सत्र में फील्ड स्तर पर आने वाली चुनौतियों एवं नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।

रेल कर्मचारियों के साथ "संवाद"

- रेल कर्मचारियों (जैसे बुकिंग क्लर्क, रिजर्वेशन क्लर्क, कमर्शियल सुपरवाइजर, कमर्शियल इंस्पेक्टर, टिकट चेकिंग स्टाफ, कैटरिंग स्टाफ एवं अन्य वाणिज्य विभाग के कर्मचारी) को अपनी समस्याओं, सुझावों एवं अनुभवों को सीधे उच्च अधिकारियों के समक्ष रखने का अवसर प्राप्त हुआ।
- फील्ड स्तर पर आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों पर चर्चा की गई तथा उनके समाधान हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
- यात्री सेवाओं में सुधार, कार्यकुशलता बढ़ाने एवं बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया।
- संवाद के दौरान यात्रियों को उपलब्ध कराई जाने वाली मूलभूत सुविधाओं जैसे पेयजल व्यवस्था, खानपान की गुणवत्ता, लिनेन की उपलब्धता एवं स्वच्छता से संबंधित मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की गई तथा सुधार हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।
- कर्मचारियों को नीतियों एवं नई पहलों की जानकारी देकर उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रेरित किया गया।
- संवाद के माध्यम से प्रशासन एवं कर्मचारियों के बीच पारदर्शिता एवं विश्वास को और सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया।

प्रमुख उपलब्धियां

पश्चिम रेलवे द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 20 मार्च 2026 तक कुल 8218.91 करोड़ का ओरिजनेटिंग यात्री राजस्व अर्जित किया गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 8.38% अधिक है। इसी अवधि में ओरिजनेटिंग यात्रियों की संख्या 1327.30 मिलियन दर्ज की गई।

अहमदाबाद मंडल ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 20 मार्च 2026 तक 1755.94 करोड़ का यात्री राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6.94% अधिक है। साथ ही, इस अवधि में 39.14 मिलियन यात्रियों को सेवाएं प्रदान की गईं।

राजस्व वृद्धि हेतु किए गए प्रमुख प्रयास

- यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा विभिन्न पहल की गईं, जिनमें प्रमुख रूप से:
- 20 मार्च 2026 तक 4,621 विशेष ट्रेन यात्राओं का संचालन किया गया, जिससे लगभग 482.57 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ तथा लगभग 49.01 लाख यात्रियों को सुविधा प्रदान की गई।
- फरवरी 2026 तक 24 जोड़ी ट्रेनों में स्थायी रूप से 58 कोचों का विस्तार किया गया।
- अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने हेतु कुल 12,674 कोचों का संवर्धन (augmentation) किया गया, जिससे 86.64 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ।
- चालू वित्तीय वर्ष में 7 नई ट्रेनों की शुरुआत की गई।

यात्री सुविधा हेतु डिजिटल पहल

- यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मुंबई मंडल द्वारा "सरल रिफंड सेवा" (SARAL Refund Sewa) नामक डिजिटल पहल शुरू की गई है।
- इस सेवा के माध्यम से असफल डिजिटल लेनदेन पर रिफंड प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब यात्री टिकट काउंटर पर उपलब्ध QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।
- "संवाद" कार्यक्रम के माध्यम से कर्मचारियों को अपने विचार एवं सुझाव सीधे उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने का अवसर मिला। यह पहल न केवल कार्यकुशलता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी, बल्कि यात्री सेवाओं में और अधिक सुधार लाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

ई-नगर पोर्टल : गुजरात शहरी विकास मिशन अंतर्गत नागरिक सेवाओं के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म

वर्ष 2025-26 में ई-नगर पोर्टल पर 18 लाख से अधिक ट्रांजेक्शन दर्ज हुए और 1031 करोड़ रुपए से अधिक आय प्राप्त हुई

▸▸ नागरिकों के लिए कर भुगतान, लाइसेंस आवेदन, विवाह पंजीकरण, मकान अनुमति, पानी व ड्रैनेज कनेक्शनों के संचालन जैसी सेवाएँ एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध

▸▸ ई-नगर पोर्टल पर कुल मिलाकर 1.24 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांजेक्शन दर्ज हुए और 6076 करोड़ रुपए से अधिक आय प्राप्त हुई

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में डिजिटल परिवर्तन का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। टेक्नोलॉजी के प्रभावी उपयोग द्वारा प्रत्येक नागरिक का जीवन सरल बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया था। आज इंटरनेट की व्यापक पहुँच तथा सरकारी सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध होने से आम नागरिक के रोजमर्रा के कार्य आसानी से पूरे हो सकते हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तथा नागरिक-केन्द्रित गवर्नेंस को नई ऊँचाइयाँ मिल रही हैं। नगर पालिका की विभिन्न सेवाएँ एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के उद्देश्य से गुजरात शहरी विकास मिशन (जीयूडीएम) द्वारा ई-नगर पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसमें वर्ष 2025-26 में 18 लाख से अधिक ट्रांजेक्शन दर्ज हुए हैं। उल्लेखनीय है कि ई-नगर पोर्टल अंतर्गत आम नागरिक शिकायत पंजीकरण, दुकान के लाइसेंस के लिए आवेदन, विवाह पंजीकरण, मकान की अनुमति, व्यवसाय कर, संपत्ति कर, एस्टेट रेंट भुगतान, हॉल बुकिंग, पानी तथा ड्रैनेज आदि कार्य घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। यह पोर्टल 24X7 ऑनलाइन एक्सेस, पेमेंट के लिए कार्ड, यूपीआई तथा नेट बैंकिंग जैसे विकल्प, रीयल-टाइम एप्लिकेशन ट्रैकिंग, मोबाइल एप्लिकेशन सपोर्ट प्रदान करता है और नागरिक प्रमाणपत्र तथा रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इतना ही नहीं; नागरिक इस पोर्टल का अधिक बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें; इसके लिए नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा

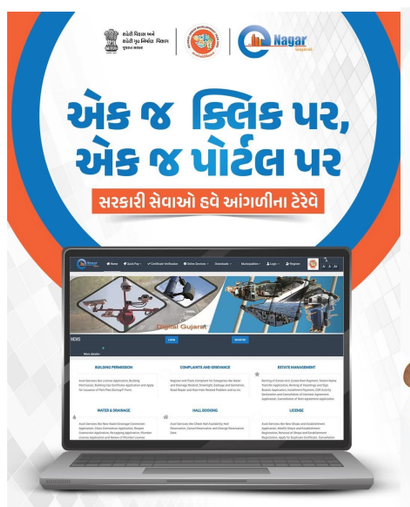

है। यूजर्स जानकारी आसान से प्राप्त कर सकें; इसके लिए पोर्टल में एआई चैटबोट की सुविधा जोड़ी गई है। इसके अलावा, भाषिणी के सहयोग से ई-नगर पोर्टल अब 23 भाषाओं में उपलब्ध है, जिसके कारण विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले लोगों के लिए इसका उपयोग सरल बना है।

गुजरात सरकार के ई-नगर प्रोजेक्ट के कारण नागरिक तथा प्रशासन के बीच संपर्क अधिक सरल एवं सुदृढ़ बना है। नागरिक अब किसी भी स्थान से फीस, टैक्स तथा अन्य शुल्कों का भुगतान कर सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं और प्रमाणपत्र ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार, राज्य सरकार की एकीकृत डिजिटल व्यवस्था द्वारा नागरिकों को तमाम सेवाएँ एक ही स्थान पर मिलती हैं।

वर्ष 2025-26 के दौरान ई-नगर पोर्टल पर 18 लाख से अधिक ट्रांजेक्शन दर्ज हुए

ई-नगर पोर्टल के कारण कागजी कार्य कम हुआ है। म्युनिसिपल ऑफिसों में लंबी कतारों में खड़े रहने की समस्या दूर हुई है और नागरिक सेवाएँ तेज व पारदर्शी बनी हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान पोर्टल पर 18 लाख से अधिक ट्रांजेक्शन दर्ज हुए हैं और 1031 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है। वर्ष 2024-25 में 26 लाख ट्रांजेक्शन तथा 1522 करोड़ रुपए की आय दर्ज हुई। कुल मिलाकर इस प्लेटफॉर्म पर 1.24 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांजेक्शन हुए हैं और 6076 करोड़ रुपए से अधिक आय प्राप्त हुई है, जो दर्शाता है कि लोग इस प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग कर रहे हैं और उनका समय भी बच रहा है।

ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और वैश्विक बाजार पर इसका प्रभाव

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका और इज़राइल के बीच छिड़ा संघर्ष पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। मिसाइलों और घातक बमों के व्यापक इस्तेमाल से इस संघर्ष की तीव्रता स्पष्ट है। क्रूरता इस हद तक पहुंच गई है कि युद्ध कानूनों का उल्लंघन करते हुए नागरिक क्षेत्रों पर बम गिराए जा रहे हैं। शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। विशेष रूप से, ईरान में एक लड़कियों के स्कूल पर बमबारी की गई, जिसमें कई छात्राओं की मौत हो गई। और यह युद्ध ईरान पर थोपा गया था। जिसका परिणाम आज पूरी दुनिया के सामने है, फिर भी कोई भी देश अमेरिका या इज़राइल से इस बारे में सवाल करने का साहस नहीं रखता। पश्चिम एशिया में जारी भीषण युद्ध के बीच, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह चिंता बढ़ रही है कि यदि स्थिति बिगड़ती रही तो आने वाले दिनों में संकट और अधिक व्यापक और गंभीर हो सकता है। वास्तविकता यह है कि इज़राइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर संयुक्त हमले के बाद युद्ध जिस दिशा में आगे बढ़ा है, उससे शांति की संभावनाएं धूमिल होती जा रही हैं। एक ओर, बीएसई सूचकांक लगभग 2500 अंक गिर गया, वहीं एनएसई निफ्टी 775 अंक गिर गया। जून 2024 के बाद इन सूचकांकों में एक दिन में दर्ज की गई यह सबसे बड़ी गिरावट है। हालांकि, इस तरह की बाजार गिरावट अक्सर विभिन्न कारकों के एक साथ आने का परिणाम होती है। इस मामले में, वैश्विक स्तर पर मूल कारण स्पष्ट है और वह यह है कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, साथ ही पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच महत्वपूर्ण ऊर्जा अवसंरचनाओं और तेल एवं गैस सुविधाओं पर हमलों में तेजी आना,इस बाजार में आई गिरावट का मुख्य कारण है। इसका निवेशकों के विश्वास पर स्वाभाविक रूप से बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जिसके कारण मौजूदा उथल-पुथल को लेकर असुरक्षा की भावना फैल गई है। दरअसल, जब से ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को अवरुद्ध किया है, वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति बाधित हो गई है। भारत समेत कई देश इस स्थिति से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और अब तेल और गैस के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में जुटे हैं। इसी संदर्भ में भारत ने रूस से तेल की खरीद बढ़ा दी है। यह आशंका भी है कि भारत की प्राकृतिक गैस आपूर्ति गंभीर रूप से बाधित हो सकती है। कतर के रास लाफान पर हुए हमले के बाद यह आशंका निराधार नहीं है। अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर संयुक्त हमला कर दिया है, लेकिन जिस तरह से तीनों देश नुकसान झेल रहे हैं,अगर यह युद्ध लंबा चलता है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारत को लकड़ी और कोयले का सहारा भी लेना पड़ेगा। अंततः, समझौता ही एकमात्र बड़ा हथियार है। लेकिन इसकी व्याख्या कौन कर सकता है?

उदयपुर: मीराबाई के बेटे की शादी में पुलिसकर्मियों ने दखल दिया, जो पिछले 25 सालों से खाना बनाने का काम कर रहा है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। पुलिसकर्मी भी आम इंसान होते हैं। वे भी आम लोगों की तरह भावनाएं, प्रेम, करुणा, दया, क्रोध आदि व्यक्त करते हैं। लेकिन यहां एक ऐसी महिला की भावुकता, प्रेम, करुणा और आत्मसम्मान की कहानी है जो जानने योग्य है। बात यह है कि उदयपुर के प्रताप नगर पुलिस स्टेशन में, 25 वर्षों से पुलिस स्टेशन में खाना बनाने वाली मीराबाई के बेटे के लिए पुलिसकर्मियों ने मामा बनकर जिम्मेदारी संभाली। रविवार शाम को, पुलिस स्टेशन के अध्यक्ष पूरनसिंह राजपुरोहित समेत सभी पुलिसकर्मी ढोल-नगाड़े बजाते हुए मीराबाई के घर पहुंचे। उस समय उन्होंने पारंपरिक ढंग से सजाई हुई थाली में ममेरू लेकर प्रवेश किया। सजी हुई थाली में कपड़े और नकदी लेकर पुलिसकर्मी मंडप पहुंचे और वर्दी के ऊपर सिर पर सफा बांधा। मीराबाई ने पुलिसकर्मियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। और जब पुलिस दल ने उन्हें प्रशंसा के प्रतीक के रूप में 1,11,000 रुपये नकद से भरी थाली भेंट की, तो मीराबाई भावुक हो गईं।

मीराबाई पिछले 25 वर्षों से पुलिस स्टेशन में रसोइया के रूप में काम कर रही हैं। और वह सभी पुलिसकर्मियों की माँ की तरह देखभाल करती हैं। उनके इस स्नेह को देखकर पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों ने मिलकर फैसला किया कि अगर पुलिसकर्मियों द्वारा उनके बेटे की शादी में मामेरू (शादी की रस्म) निभाई जाए, तो यह समाज में एक अलग मिसाल कायम करेगा। मीराबाई बताती हैं कि जब उनका बेटा मुकेश छह महीने का था, तब उनके पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अकेले ही कड़ी मेहनत करके अपने बेटे का पालन-पोषण किया है।

इस प्रकार, यह मामला पुलिस के दूसरे पहलू का एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, जो पुलिस को उजागर करने के साथ-साथ पुलिसकर्मियों को भी मानवीय रूप में प्रस्तुत करता है।

मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में वातानुकूलित कोचों की स्थायी वृद्धि, यात्रियों को मिलेगी अतिरिक्त सुविधा

यात्रियों की सुविधा एवं रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक मेल/एक्सप्रेस ट्रेन में न्यूनतम 06 स्लीपर श्रेणी कोच उपलब्ध कराने तथा वातानुकूलित कोचों की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे द्वारा भावनगर मंडल से होकर चलने वाली मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की संरचना में स्थायी रूप से वातानुकूलित श्रेणी कोचों की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस निर्णय से वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त स्थान उपलब्ध होगा तथा भीड़ प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार संशोधित कोच संरचना का विवरण निम्नानुसार है —

1. गाड़ी संख्या 19217/19218 बान्द्रा टर्मिनस-वेरावल एक्सप्रेस संशोधित संरचना के अनुसार थर्ड एसी कोचों की संख्या 6 से बढ़ाकर 7 किए जाएंगे। ये कोच बान्द्रा टर्मिनस से 22 मई, 2026 से तथा वेरावल से 23 मई 2026 से प्रभावी होंगे।

2. गाड़ी संख्या 12971/12972 बान्द्रा टर्मिनस-भावनगर के ट्रेन संरचना में संशोधन कर थर्ड एसी श्रेणी कोचों की संख्या 6 से बढ़ाकर 7 की जाएगी। ये कोच भावनगर टर्मिनस से 21 मई, 2026 से तथा बान्द्रा टर्मिनस से 24 मई, 2026 से प्रभावी होंगे।

3. गाड़ी संख्या 19271/19272 भावनगर-हरिद्वार एक्सप्रेस में संशोधित संरचना के अनुसार थर्ड एसी श्रेणी कोचों की संख्या 6 से बढ़ाकर 7 किए जाएंगे। ये कोच भावनगर टर्मिनस से 21 मई, 2026 से तथा हरिद्वार से 23 मई, 2026 से प्रभावी होंगे।

4. गाड़ी संख्या 12941/12942 भावनगर-आसनसोल सुपरफास्ट में संशोधित संरचना के अनुसार थर्ड एसी श्रेणी कोचों की संख्या 6 से बढ़ाकर 7 किए जाएंगे। ये कोच बान्द्रा टर्मिनस से 22 मई, 2026 से तथा वेरावल से 23 मई 2026 से प्रभावी होंगे।

5. गाड़ी संख्या 22963/22964 बान्द्रा टर्मिनस-भावनगर सुपरफास्ट में संशोधित संरचना के अनुसार थर्ड एसी श्रेणी कोचों की संख्या 6 से बढ़ाकर 7 किए जाएंगे। ये कोच भावनगर टर्मिनस से 26 मई, 2026 से तथा आसनसोल से 28 मई, 2026 से प्रभावी होंगे।

6. गाड़ी संख्या 19319/19320 वेरावल-इंदौर एक्सप्रेस में संशोधित संरचना के अनुसार थर्ड एसी श्रेणी कोचों की संख्या 6 से बढ़ाकर 7 किए जाएंगे। ये कोच भावनगर टर्मिनस से 24 मई, 2026 से तथा बान्द्रा टर्मिनस से 25 मई, 2026 से प्रभावी होंगे।

6. गाड़ी संख्या 19319/19320 वेरावल-इंदौर एक्सप्रेस में संशोधित संरचना के अनुसार थर्ड एसी श्रेणी कोचों की संख्या 6 से बढ़ाकर 7 किए जाएंगे। ये कोच इंदौर से 26 मई, 2026 से तथा वेरावल से 27 मई, 2026 से प्रभावी होंगे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के समक्ष नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं के ऑनलाइन निवारण का मार्च महीने का राज्य स्तरीय 'स्वागत' बुधवार, 25 मार्च को आयोजित होगा

गुरुवार, 26 मार्च को राम नवमी के सार्वजनिक अवकाश को ध्यान में रखते हुए मार्च-2026 का राज्य स्तरीय 'स्वागत' बुधवार को होगा

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में हर महीने आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय स्वागत ऑनलाइन जनशिकायत निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च-2026 का राज्य स्तरीय 'स्वागत' (स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रिवेंसेस बाई एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी) कार्यक्रम बुधवार, 25 मार्च को आयोजित होगा।

ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से वर्ष 2003 से शुरू हुआ स्वागत ऑनलाइन जनशिकायत निवारण कार्यक्रम के तहत हर महीने के चौथे गुरुवार को राज्य स्तरीय स्वागत का आयोजन किया जाता है।

मार्च महीने के चौथे गुरुवार, 26 मार्च को राम नवमी के सार्वजनिक अवकाश को ध्यान में रखते हुए मार्च-2026 का राज्य स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम इस बार बुधवार, 25 मार्च को आयोजित करने का निर्णय किया गया है।

इस 'स्वागत' कार्यक्रम के लिए नागरिक अपने अभ्यावेदन बुधवार, 25 मार्च की सुबह 8:00 से 11:00 बजे के दौरान मुख्यमंत्री की जनसंपर्क इकाई, स्वर्णिम संकुल-2, गांधीनगर में व्यक्तिगत रूप से दे सकते हैं।

मुख्यमंत्री दोपहर बाद इस राज्य स्तरीय 'स्वागत' में स्वयं उपस्थित रहकर नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे।

सत्यमेव जयते
गुजरात सरकार

स्वस्थ गुजरात, समृद्ध गुजरात

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए
₹25,403 करोड़ का प्रावधान

विकसित भारत
गुजरात बजट 2026-27
विकसित गुजरात

+ प्रधानमंत्री जन आरोग्य-मुख्यमंत्री अमृतम् (PMJAY-MA) के अंतर्गत **₹3,472 करोड़** का आवंटन
+ G.M.E.R.S. संचालित मेडिकल अस्पतालों के लिए **₹1,851 करोड़** का प्रावधान
+ अहमदाबाद और सूरत में मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल तथा कैंसर, कार्डियक-न्यूरो, यूरो-नेफ्रो सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के लिए **₹500 करोड़** का प्रावधान
+ पी.डी.यू. अस्पताल, राजकोट में 1,000 बेड क्षमता वाले अस्पताल के लिए **₹90 करोड़** का प्रावधान
+ वलसाड, डांग, नर्मदा, छोटा उदयपुर और कच्छ जिलों में 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए **₹28 करोड़** का प्रावधान
+ इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर, अहमदाबाद तथा सैटेलाइट केंद्र सूरत, सोला (अहमदाबाद), गांधीनगर और भावनगर के लिए **₹186 करोड़** का आवंटन
+ यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च, अहमदाबाद तथा सैटेलाइट केंद्र सूरत, सोला (अहमदाबाद), गांधीनगर, भावनगर, राजकोट और पोरबंदर के लिए **₹167 करोड़** का प्रावधान
+ गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद तथा सैटेलाइट केंद्र राजकोट, भावनगर, पोरबंदर, वलसाड, सिद्धपुर, हिम्मतनगर और गोधरा के लिए **₹153 करोड़** का आवंटन

"राज्य के हर नागरिक को अपने घर के पास ही विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हों, यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अत्याधुनिक सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों से लेकर ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों तक की ये सभी बजटीय व्यवस्थाएँ गुजरात के हर परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करेंगी।"

- श्री हर्ष संघवी, माननीय उपमुख्यमंत्री, गुजरात